नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

98 करोड़ की फीस ने पेट्रोल पंप संचालकों की उड़ाई नींद

यूपीआई पर 2000 से ऊपर के लेने-देन से पंप संचालकों की कटेगी जेब

प्रांजुल पांडेय

भोपाल, 21 सितंबर. यूपीआई के जरिए 2000 से ज्यादा के भुगतान पर लगने वाले एमडीआर ने देश भर के पेट्रोल पंप डीलरों की नींद उड़ा दी है.

सरकार का दावा है कि यह फीस सुरक्षित लेनदेने के एवज में ली जा रही है. लेकिन, पंप डीलरों का मानना है कि इसका असर सीधे उन पर पड़ेगा. अन्य कारोबार में व्यापारी इसे ग्राहकों से अनधिकृत तौर वसूल सकते हैं. उनकी इस घबराहट की वजह करोड़ों रुपए का सीधा वह बोझ है जो उनकी जेब पर अचानक पड़ने वाला है. सिर्फ मध्य प्रदेश की ही बात करें तो प्रदेश में करीब 4700 पेट्रोल पंप है जो एमडीआर के दायरे में आने वाले हैं. जिन पर 16 अक्टूबर से लगने वाली फीस से करीब 98 करोड़ रुपये की देनदारी आएगी.

डीलरों पर ऐसे पड़ेगा बोझ

- 2000 रुपए से अधिक यूपीआई लेन-देन - 5 रुपए एमडीआर
- 18 प्रतिशत जीएसटी - .90 पैसे
- 1 लेनदेन पर कुल फीस - 5 .90 रुपए
- 100 लेन-देन औसतन एक पंप पर - 590 रुपए प्रतिदिन फीस
- 1 महीने में अतिरिक्त भार - 17,400 रुपए
- 4700 पंप हैं प्रदेश में - 27 .73 लाख रुपए प्रतिदिन
- 1 महीने में अतिरिक्त भार - 8 .17 करोड़ रुपए
- 1 साल में अतिरिक्त भार - 98 करोड़ रुपए

1 .02 लाख पंपों पर असर

देश के करीब 1.02 लाख पेट्रोल पंपों पर एमडीआर का असर पड़ेगा. इनमें उप 13,165, महाराष्ट्र में 9,267, तमिलनाडु में 8,042, कर्नाटक में 7,512, राजस्थान में 7,407, गुजरात में 6,635, आंध्रप्रदेश में 4,983, तेलंगाना में 4,570 पंप हैं. जिन पर करीब 5 .10 करोड़ रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

10 अक्टूबर तक समाधान की उम्मीद

सरकार और तेल कंपनियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है. उम्मीद है कि 10 अक्टूबर तक समाधान निकलेगा. यदि समाधान नहीं हुआ तो 16 अक्टूबर से नकद लेनदेन करेंगे.

अजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन

भर्तियों के लिए आउटसोर्स का सहारा लेगी सरकार

1. **पीएससी और पीईबी के पास काम के दबाव के चलते विभागों को रियायत देने की तैयारी**
2. **स्वास्थ्य विभाग का फार्मूला दूसरे विभागों में भी हो सकता है लागू**
3. **चुनाव से पहले अलग- अलग विभागों में डेढ़ लाख से अधिक पद भरने की तैयारी**

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 सितंबर. विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता में है. संभावना है कि कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक कम से कम डेढ़ लाख पद भरे जाएंगे, वैसे तो सरकारी दावा दो लाख से अधिक पदों का है. इतने अधिक पदों पर भर्ती की कवायद के चलते पहले ही मप्र लोक सेवा आयोग और प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी दबाव में चल रहे हैं. दोनों के परीक्षा के कैलेंडर के हिसाब से अगले दो वर्ष तक का स्लॉट बुक है.कोई अतिरिक्त परीक्षा कराने के लिए न तो तैयार हैं और न ही उनके पास इतना समय है. राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

विभाग का फार्मूला दूसरे विभागों में भी लागू कर सकती है. जिसके तहत अब दूसरे विभागों को भी विभागीय भर्ती परीक्षा कराने के लिए एजेंसी आउटसोर्स करने की अनुमति मिल सकती है.

राज्य सरकार ने पहले नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चुनिंदा पदों की अपने स्तर पर भर्ती के लिए अधिकार दे दिए हैं. कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की कमी के चलते विभाग को ही अपने स्तर पर भर्ती करने की छूट दी है.ऊर्जा विभाग में भी 6 हजार पदों पर विभागीय भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा कराने की रियायत मिली हुई है. इसी तरह एक और विभाग में शामिल नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भी 400 इंजीनियरों की भर्ती के लिए पीएससी के बजाय भारत सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी से संपर्क किया है. जिससे कि कम समय में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा सके. नगरीय प्रशासन विभाग को तो केंद्र सरकार की अधिकृत एजेंसी एजुकेशन कंसल्टेंड इंडिया ने महज चार माह में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आश्वस्त कर दिया है.

घूस मांगने पर विपणन अधिकारी को किया सस्पेंड

सीहोर के दो निजी वेयरहाउस के संचालकों की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री का एक्शन

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 21 सितंबर. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मंत्रालय के एक विपणन अधिकारी अनुराग को सीहोर जिले के दो निजी वेयरहाउस के संचालकों से सब्सिडी पास करने

के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया है. मंत्रालय के विपणन अधिकारी अनुराग सीहोर जिले के दौरे पर था. इस दौरान उसने दो निजी वेयरहाउस का निरीक्षण किया और वहां संचालकों से सब्सिडी पास करने के बदले अवैध राशि की मांग की. अधिकारी ने भैरुंदा तहसील में स्थित शिवाय वेयरहाउस के संचालक से 1 लाख रुपये और रेहटी क्षेत्र के ग्राम बेहराखेड़ी में स्थित श्री कृष्णा वेयरहाउस से 60 हजार की घूस मांगी थी.

दतिया की महिला आरटीओ इंस्पेक्टर की भोपाल में हत्या

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 21 सितंबर. खजूरी सड़क इलाके में दतिया में पदस्थ 45 वर्षीय महिला आरटीओ इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले की उनके दोस्त पवन कुमार द्विवेदी ने रविवार रात हथौड़े से वार कर हत्या कर दी. वारदात करने के बाद पवन ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिए. पुलिस हत्या और खुदकुशी के पूरे मामले की जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक मीनाक्षी रविवार को अपनी तीन साल की बेटी और केयरटेकर रितिका साहू के साथ भोपाल पहुंची. वे यहां खजूरी सड़क इलाके के लेकपर्ल कॉलोनी में पवन कुमार द्विवेदी के

दोस्त ने सिर पर मारा हथौड़ा और की खुदकुशी

किराए के मकान पर रुके थे. सीधी जिले का रहने वाला पवन इस मकान में अकेला रहता था. मीनाक्षी की केयरटेकर रितिका ने पुलिस को बताया कि देर रात खाना खाकर वह करीब 10 बजे मीनाक्षी की बेटी को साथ में लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई. सोमवार सुबह के करीब 5.30 बजे रितिका, जब सो कर उठी तो हाल में उसने खून से लथपथ मीनाक्षी और मकान के पास लगे पेड़ पर फंदे पर पवन का शव लटका देखा. रितिका ने इसकी सूचना तुरंत ही मीनाक्षी की बहन हस्तलेखा को फोन पर दी.

गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई टली

जबलपुर. भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में जेल में बंद आरोपी सास पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायालयीन कार्य की अधिकता और समयाभाव के कारण कोर्ट ने मामले को 24 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है.

खरगापुर के निजी हॉस्टल से तीन नाबालिग बच्चे लापता

टीकमगढ़/खरगापुर, 21 सितंबर. टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में गल्ला मंडी के पास स्थित एक निजी हॉस्टल से तीन नाबालिग बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. परिजनों की शिकायत पर खरगापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चों

की तलाश शुरू कर दी है. लापता बच्चों की पहचान आनंद अहिरवार (13 वर्ष), विशाल कुशवाहा (12 वर्ष) और प्रमोद कुशवाहा (9 वर्ष) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे बीती रात हॉस्टल में ही सोए थे. सुबह जब हॉस्टल में उनकी तलाश की गई तो तीनों बच्चे वहां मौजूद नहीं मिले. इसके बाद हॉस्टल प्रबंधन की ओर से परिजनों को जानकारी दी गई. बच्चों के नहीं मिलने की सूचना मिलते ही परिजन खरगापुर थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है.

हॉस्टल की देखरेख करने वाले से पूछताछ : जानकारी के अनुसार यह निजी हॉस्टल खरगापुर गल्ला मंडी के पास स्थित है और इसकी देखरेख रमेश अहिरवार द्वारा की जाती है. बच्चों के लापता होने के मामले में पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

खरगापुर थाना प्रभारी अम्बर सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस टीम हॉस्टल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चे हॉस्टल से कब और किस दिशा में गए.

Creative Visualisation. Images used are for illustration purposes only. | Applicable T&C available at the dealership. | **As certified by Kantar IMRB for an OEM platform for end-to-end usage as on November 28, 2025. | #543 km range: Certified range; actual results may vary by driving conditions and usage. | Assured buyback plan is available on payment basis with the option of 3 years/45 000 km or 4 years/60 000 km ownership plans (whichever is earlier). The program is offered through an insurance company. e VITARA comes with standard warranty of 3 years/1 00 000 km (whichever is earlier) with an option of extending the same on payment basis to 5 years/1 40 000 km and service activated coverage for 6th to 8th year for EV related components.